# Financial Inclusion

Provision of access to financial services to low-income households and small businesses has been a long standing goal of Government of India. The 'Committee on Comprehensive Financial Services for Small Businesses and Low Income Households' had observed that on aspects of both Financial Inclusion and Financial Depth, the overall situation was very poor and, on a regional and sectoral basis, very uneven. Financial Inclusion is defined as the spread of financial institutions and financial services across the country while Financial Depth is defined as the percentage of credit to GDP at various levels of the economy. Majority of small businesses have no links with formal financial institutions and close to half of the rural and urban population do not even have a functional bank account. There is high demand for a wide range of financial services by small businesses and low-income households combined with a willingness to pay for them. The challenge is clearly the ability of the formal financial system to mount a strong supply response, which needs to be strengthened considerably. It is in this context that the role of Post Office towards Financial Inclusion needs to be understood.

The Post Office Savings Bank (POSB) founded in 1873 to promote thrift and savings, much before commercial banks made their appearance, is the sheet anchor of financial inclusion in India. With a spread across 155,000 Post Offices it has been rendering yeoman service to the nation.

On 15 August, 2016 the Prime Minister announced the setting up of India Post Payments Bank (IPPB) during his 70th Independence Day address to the nation from the Red Fort. The subsequent incorporation of the bank, grant of the final license by the Reserve Bank of India and launch of two pilot branches on 30 January, 2017 have brought to fruition the long standing quest of the Post Office to contribute its might to the formal banking sector.

IPPB is committed to achieving the objective of financial inclusion in India. The motto of the bank, 'Aapka Bank Aapke Dwar' will translate into more than three lakh Postmen and Gramin Dak Sewaks providing assisted banking at door steps in rural, urban and remote areas particularly to those not familiar with technology such as the rural poor and the elderly. The bank is focussing on equipping and enabling small merchants and vendors to accept cashless payments and thereby foster a digital acceptance ecosystem. IPPB is creating infrastructure at the last mile to strengthen and deepen DBT. The association with India Post and the Dakiya infuses trust and confidence amongst users to try out electronic banking, including UPI. IPPB will make banking and payments simple. Using technology, it simplifies opening of accounts in minutes and allows customers to make digital transactions with the help of QR Cards and biometric authentication. The bank also runs financial literacy programmes to teach electronic banking to those not comfortable with Information technology based applications including homemakers, farmers and workers. IPPB enables the post office to accept digital payments at counters, offer small savings schemes online (NSC/KVP/PPF) and increase its footprint in the e-commerce world by providing electronic cash on delivery options to its customers at their door step.

In perspective, the IPPB is a seminal part of the objective of the Government of India to promote financial inclusion of the weakest and least accessed segments of the country. It is a critical building block of the Government of India's financial inclusion strategy.

Since the nationwide launch of IPPB by the Prime Minister on 1st September, 2018 the bank has expanded its network from 350 branches and 3250 access points to 1,19,640 access points as on 14-01-2019. In the process, the banking network of the country has doubled while the bank network has increased by 2.5 times.

Department of Posts is pleased to issue a Commemorative Postage Stamp on Financial Inclusion.

## Credits:


| | |
|---|---|
| Text | : Based on the information received from PBI Division, Department of Posts |
| Stamp | : Shri Satish Gujral |
| FDC/ Brochure | : Shri Kamleshwar Singh |
| Cancellation Cachet | : Smt. Alka Sharma |


भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS INDIA

विवरणिका BROCHURE

# वित्तीय समावेशन

# Financial Inclusion

# वित्तीय समावेशन

कम–आय वाले परिवारों और लघु व्यवसायों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था करना भारत सरकार का लंबे समय से लक्ष्य रहा है। 'लघु व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं संबंधी समिति' ने यह पाया था कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय गहराई के दोनों पहलुओं पर समग्र स्थिति बहुत खराब थी और क्षेत्रीय और सेक्टर आधार पर अत्यधिक असमान थी। वित्तीय समावेशन को देशभर में वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थाओं के विस्तार के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि वित्तीय गहराई को अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर जीडीपी की तुलना में ऋण (क्रेडिट) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिकतर लघु व्यवसायों का औपचारिक वित्तीय संस्थानों से कोई संबंध नहीं है और ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की लगभग आधी जनसंख्या का कोई सक्रिय बैंक खाता भी नहीं है। लघु व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों द्वारा विविध वित्तीय सेवाओं के लिए अत्यधिक मांग रही है और वे इन सेवाओं के बदले भुगतान करने को तैयार हैं। यह, औपचारिक वित्तीय सिस्टम की क्षमता के लिए स्पष्टतः एक चुनौती है, जिसे इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में, वित्तीय समावेशन की दिशा में डाकघर की भूमिका को समझने की आवश्यकता है।

वाणिज्यिक बैंकों की शुरुआत से काफी पहले, बचतों को बढ़ावा देने के लिए 1873 में स्थापित डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी), भारत में वित्तीय समावेशन का अवलम्ब है। यह, देशभर में 1,55,000 डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्र को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता रहा है।

15 अगस्त, 2016 को 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना के संबंध में घोषणा की थी। तत्पश्चात, बैंक की स्थापना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम रूप से लाइसेंस प्रदान किए जाने और 30 जनवरी, 2017 को दो पायलट शाखाओं के शुभारंभ से, डाकघरों की औपचारिक बैंकिंग सेक्टर में अपना योगदान करने की लंबे समय से रही चाह पूरी हुई है।

आईपीपीबी भारत में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तीन लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण, शहरी तथा दूर–दराज के क्षेत्रों में विशेषतः निर्धन ग्रामीण और वृद्धजनों, जिन्हें प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं है, के द्वार पर बैंकिंग सहायता प्रदान कर इस बैंक के आदर्श–वाक्य, 'आपका बैंक आपके द्वार' को मूर्त–रूप देंगे। यह बैंक लघु–व्यापारियों तथा वेंडरों को नकदी रहित भुगतानों को स्वीकार करने के लिए उपकरणों से लैस एवं समर्थ बनाने पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार, आईपीपीबी डीबीटी को सशक्त एवं मजबूत बनाने के लिए अंतिम छोर तक बैंकिंग अवसंरचना का निर्माण करेगा। यूपीआई सहित, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के इस्तेमाल के लिए, भारतीय डाक तथा डाकिए के साथ सहयोग, प्रयोक्ताओं के बीच भरोसा एवं विश्वास पैदा करेगा। आईपीपीबी बैंकिंग तथा भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, इसमें मिनटों में खाता खोला जा सकेगा तथा इसमें क्यू.आर. कार्डों तथा बायोमीट्रिक प्रमाणन की सहायता से ग्राहक डिजिटल लेन–देन कर सकेंगे। यह बैंक, गृहणियों, किसानों तथा कामगारों सहित ऐसे लोगों को, जो सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ऐप्लिकेशन में सहज कार्य नहीं कर पाते, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की जानकारी प्रदान करने के लिए, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन करेगा। आईपीपीबी, काउंटरों पर डिजिटल भुगतानों को स्वीकार करने, लघु बचत स्कीमों (एनएससी/केवीपी/पीपीएफ) को ऑनलाइन प्रदान करने तथा ग्राहकों को उनके द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक कैश ऑन डिलिवरी का विकल्प प्रदान कर, ई–कॉमर्स में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में डाकघरों को समर्थ बनाएगा।

इस परिप्रेक्ष्य में, देश के अत्यधिक कमजोर तथा सुविधाओं से वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आईपीपीबी भारत सरकार के उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह भारत सरकार के वित्तीय समावेशन की रणनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

प्रधानमंत्री द्वारा 01 सितम्बर, 2018 को आईपीपीबी का देशव्यापी शुभारंभ किया गया। 350 शाखाओं और 3250 सेवा केन्द्रों के साथ प्रारंभ हुए इस बैंक के नेटवर्क का निरंतर विस्तार हो रहा है। 14.01.2019 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,19,640 सेवा केन्द्र प्रचालनरत हैं। इस प्रकार, देश में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार दोगुना हुआ है, जबकि आईपीपीबी के नेटवर्क में 2.5 गुणा की बढ़ोतरी हुई है।

डाक विभाग, वित्तीय समावेशन पर स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।


## आभार:

| | |
|---|---|
| पाठ | : पीबीआई डिवीजन, डाक विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर |
| डाक–टिकट | : श्री सतीश गुजराल |
| प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका | : श्री कमलेश्वर सिंह |
| विरूपण मोहर | : श्रीमती अलका शर्मा |


भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS
INDIA


तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| मूल्यवर्ग<br>Denomination | : 500 पैसा<br>: 500 p |
| मुद्रित डाक-टिकटें<br>Stamps Printed | : 5.0 लाख<br>: 5.0 Lakh |
| मुद्रण प्रक्रिया<br>Printing Process | : वेट ऑफसेट<br>: Wet Offset |
| मुद्रक<br>Printer | : प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद<br>: Security Printing Press, Hyderabad |

For more information visit:
http://www.epostoffice.gov.in



मूल्य : ₹5.00